

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2019

No. 57/2019—Central Tax

G.S.R. 874(E).—In exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.28/2019 – Central Tax, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 454(E), dated the 28th June, 2019, namely:—

In the said notification, for the proviso to the first paragraph, the following proviso shall be substituted, namely: –

“Provided that for registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or current financial year, for each of the months from July, 2019 to September, 2019 till 30th November, 2019.”

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 15th Day of November, 2019.

[F. No. 20/06/09/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 28/2019 – Central Tax, dated the 28th June, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 454(E), dated the 28th June, 2019 and was subsequently amended by notification No. 53/2019 – Central Tax, dated the 14th November, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 847(E), dated the 14th November, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2019

सं. 58/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 875(अ).—आयुक्त परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 46/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 769(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्तियों के व्यौरे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग की दशा में, जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, अक्टूबर, 2019 मास के लिये, समय-सीमा, 30 नवंबर, 2019 तक है।”

2. यह अधिसूचना 11 नवंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 46/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 769(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।